

डिफेंस सेक्टर में 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश, मिलेंगी 60 हजार नौकरियां : योगी

सीएम ने कहा, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए जितनी भूमि चाहिए उतनी देंगे

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक हमारे साथ देश और दुनिया के अलग-अलग भागों से 57 एमओयू हो चुके हैं। इनके माध्यम से करीब 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश सिर्फ डिफेंस सेक्टर से ही होने जा रहे हैं। जिससे 60 हजार नौजवानों को नौकरी मिलेगी। वहीं हमारा लक्ष्य डिफेंस कॉरिडोर में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश कराना और एक लाख युवाओं को रोजगार देना है।

मुख्यमंत्री रविवार को लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर नोड में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि कानपुर में सेना के लिए गोला-बारूद के उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया, अब उसके विस्तार के लिए भी भूमि मांगी जा रही है। लखनऊ में भी ब्रह्मोस को जैसे ही 200 एकड़ भूमि दी तो पीटीसी ग्रुप भी आ गया है। 2013-14 के मुकाबले भारत का रक्षा उत्पादन कई सौ गुना बढ़ गया है।

डिफेंस में आयात निर्भरता से मुक्त होगा देश : इस दौरान पीटीसी ग्रुप के 50 एकड़ वाले परिसर में टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन और 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। बता दें कि भारत लंबे समय से एयरफ्रेम्स, मिसाइल और टर्बाइन इंजनों जैसे रक्षा प्लेटफॉर्म के लिए विशेष सामग्री आयात करता रहा है।



लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर नोड में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का रविवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को ब्रह्मोस मिसाइल का प्रतिरूप भेंट कर सम्मानित किया गया। -अमर उजाला

उत्तर प्रदेश अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा

योगी ने कहा कि यूपी देश की रक्षा उत्पादन की आत्मनिर्भरता में अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। यहां डीआरडीओ या ब्रह्मोस जैसे रक्षा उत्पादन से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के लिए जितनी भी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, प्रदेश सरकार पहले की तरह इसमें भरपूर मदद करेगी। इस अवसर पर सीएम ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल का प्रतिरूप भी भेंट किया गया। इस अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्य और ब्रजेश पाठक, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सांसद ब्रजलाल, विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह समेत डीआरडीओ, ब्रह्मोस एयरोस्पेस, पीटीसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

यह नया स्ट्रैटेजिक कॉम्प्लेक्स इस आयात निर्भरता से मुक्त कराएगा और वैश्विक संकटों से उबरने की ताकत देगा। इस अवसर पर यूके स्थित ट्राक प्रिंसिजन सॉल्यूशंस का भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में औपचारिक प्रवेश भी होगा। यह भारत को पहली बार सिंगल क्रिस्टल एयरफॉइल्स के निर्माण से लेकर फाइनल मशीनिंग तक की क्षमता प्रदान करेगा।

बता दें कि भारत हर वर्ष 14 हजार करोड़ रुपये के रक्षा-ग्रेड मेटेरियल्स आयात करता है, जो 2026 तक 35 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है। एयरोलॉय टेक्नोलॉजीज का यह कॉम्प्लेक्स इस निर्भरता को खत्म करने और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। भारत को उन देशों में शामिल करेगा, जिनके पास रक्षा मेटेरियल्स की फुल-स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी है।



राष्ट्र की भावी सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'ब्रह्मोस' मिसाइल परियोजना हेतु भूमि आवंटित कराई गई थी। आज मुख्यमंत्री ने मंच से उस ऐतिहासिक निर्णय का स्मरण करते हुए मेरी भूमिका की सराहना की और रक्षा मंत्री

भी वर्चुअल माध्यम से इस महत्वपूर्ण अवसर से जुड़े। यह क्षण केवल व्यक्तिगत संतोष का नहीं, बल्कि उस सामूहिक संकल्प की पुष्टि भी है, जो हम सबने देश की रक्षा, आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास की दिशा में एकजुट होकर लिया था। - सतीश महाना, विधानसभा अध्यक्ष